

EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 143] No. 143] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 13, 2007/आषाढ़ 22, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 2007/ASADHA 22, 1929

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 जुलाई, 2007

सं. टीएएमपी/8/2003-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार चेन्नई पत्तन न्यास पर स्टीवडोरिंग गतिविधियों के लिए लेबी की वैधता को 30 सितंबर, 2007 तक बढ़ाता है।

अनुसूची

मामला सं. टीएएमपी/8/2003-सीएचपीटी

आदेश

(जून, 2007 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने चेन्नई प्रतन न्यास पर स्टीवडोरिंग गतिविधियों के लिए लेवी की वैधता को 30 जून, 2007 तक अथवा संशोधित दरों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक बढ़ाते हुए दिनांक 25 जनवरी, 2007 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 7 फरवरी, 2007 को भारत का राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। उक्त आदेश में सीएचपीटी को यह भी निदेशित किया गया था कि वे आदेश की अधिसूचना तिथि से 15 दिनों के भीतर स्टीवडोरिंग लेवी की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करें।

- 2.1. सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 जून, 2007 द्वारा स्टीवडोरिंग लेवी की समीक्षा हेतु प्रस्ताव दाखिल किया है ।
- 2.2. वर्तमान स्टीवडोरिंग लेवी की वैधता 30 जून, 2007 को समाप्त हो जाती है। सीएचपीटी द्वारा दाखिल किया गया प्रस्ताव विचाराधीन है और संबद्ध प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठनों को परिचालित करने की प्रक्रिया में है। इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचाराधीन हेतु परिपक्व होने के लिए इस-मामले में समय लगेगा। इसलिए, वर्तमान स्टीवडोरिंग लेवी की वैधता को 30 जून, 2007 से आगे बढ़ाना आवश्यक है।
- 3. इसके परिणामस्वरूप और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीएचपीटी में प्रचलित स्टीवडोरिंग लेवी की वैधता को 30 सितंबर, 2007 तक अथवा स्टीवडोरिंग लेवी की समीक्षा हेतु सीएचपीटी से प्राप्त प्रस्ताव पर पारित होने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक इस शर्त पर बढ़ाता है कि आदेश सं. टीएएमपी/63/2004-सीएचपीटी, दिनांक 25 जनवरी, 2007 के हुक स्थल प्रेषण के लिए सी एण्ड एफ उगाही की वसूली के मामले में स्पष्टीकृत स्थिति को भी विस्तारित वैधता की अविध के दौरान अपनाया जायेगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2007/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th July, 2007

No. TAMP/8/2003-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the levy for Stevedoring activity at the Chennai Port Trust upto 30 September, 2007 as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

No. TAMP/8/2003-CHPT

ORDER

(Passed on this 28 day of June, 2007)

This Authority had passed an Order on 25 January, 2007 extending the validity of the levy for stevedoring activity at Chennai Port Trusts (CHPT) till 30 June, 2007 or till effective date of implementation of the revised rates, whichever is earlier. The Order was notified in the Gazette of India on 7 February, 2007. In the said Order, the CHPT was also directed to file its proposal for review of the stevedoring levy within 15 days from the date of Notification of the Order.

- 2.1. The CHPT vide its letter dated 5 June, 2007 has filed the proposal for review of the stevedoring levy.
- 2.2. The validity of the existing stevedoring levy expires on 30 June, 2007. The proposal filed by CHPT is under consideration and is in the process of being circulated to the relevant users/user organizations. It will take time for the case to mature for final consideration by this Authority. It is, therefore, necessary to extend the validity of the existing stevedoring levy beyond 30 June, 2007.
- 3. In the result and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing stevedoring levy at CHPT till 30 September, 2007 or till the effective date of implementation of the Order to be passed on the proposal of CHPT for review of the stevedoring levy whichever is earlier subject to the condition that the position clarified in the case of levy of C & F levy for hook point dispatch in the Order No. TAMP/63/2004-CHPT dated 25 January, 2007 would also be followed during the extended validity period.

A.L. BONGIRWAR, Chairman [ADVT. III/IV/143/2007/Exty.]